

09-09-17

प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश।

परिवादी सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा मालनपुर की ओर से शाखा प्रबंधक उमाशंकर यादव सहित अधिवक्ता श्री रवि मुदगल उप0।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री डी0आर0 बंसल।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित, परिवादी के छायाचित्र युक्त राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 147 एन0आई0 एक्ट मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। परिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री रवि मुदगल एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री बंसल द्वारा की गयी।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

परिवादी ने राजीनामा आवेदन के माध्यम से निवेदन किया है कि उसने अभियुक्त की वित्तीय स्थिति को देखते हुए चैक राशि में से मात्र कुछ राशि का भुगतान कराकर नरमी बरतते हुए राजीनामा की सहमति दी है। अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्त पर धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि न्यायालय की अनुमति से शमनीय हैं।

न्यायदृष्टांत **दामोदर एस.प्रभु विरुद्ध सैयद बाबा लाल ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 1907** तीन न्याय मूर्ति गण की पीठ के मामले में समझौते पर निम्नानुसार परिचय लगाने के निर्देश दिये हैं :-

1. यदि अभियुक्त प्रकरण का सूचना पत्र मिलने के बाद पहली या दूसरी सुनवाई पर समझौता आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तब उस पर कोई परिचय नहीं लगाया जायेगा।
2. यदि अभियुक्त पहली या दूसरी सुनवाई तिथि के बाद विचारण न्यायालय में समझौता आवेदन लगाता है तो उस पर चैक की राशि का दस प्रतिशत परिचय लगाया जा सकेगा। .....

उक्त परिचय जिस स्तर के न्यायालय पर समझौता होता है वहां के विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाना होता है। लेकिन न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कारण लिखते हुए उक्त परिचय कम कर सकती है।

**“Caselaw:- Madhya Pradesh State Legal Services Authority v. Prateek Jain and another (2014) 10 SCC 690 : 2015 (2) MPLJ 104 : JT 2014 (10) SC 413**

**Para 26.** Having regard thereto, we are of the opinion that even when a case is decided in Lok Adalat, the requirement of following the guidelines contained in **Damodar S. Prabhu AIR 2010 SC 1907: 2010 Indlaw SC 334** (supra) should normally not be dispensed with. However, if there is a special/specific reason to deviate therefrom, the

Court is not remediless as Damodar S. Prabhu 2010 (supra) itself has given discretion to the concerned Court to reduce the costs with regard to specific facts and circumstances of the case, while recording reasons in writing about such variance. Therefore, in those matters where the case has to be decided/settled in the Lok Adalat, if the Court finds that it is a result of positive attitude of the parties, in such appropriate cases, the Court can always reduce the costs by imposing minimal costs or even waive the same. For that, it would be for the parties, particularly the accused person, to make out a plausible case for the waiver/reduction of costs and to convince the concerned Court about the same. This course of action, according to us, would strike a balance between the two competing but equally important interests, namely, achieving the objectives delineated in Damodar S. Prabhu (supra) on the one hand and the public interest which is sought to be achieved by encouraging settlements/resolution of case through Lok Adalats."

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में इस प्रकरण को देखने से यह दर्शित है कि प्रकरण दिनांक 23.07.07 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 04.08.07 को पंजीबद्ध हुआ। प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना है। चैक राशि मात्र 10574 रुपये है जिससे कम में राजीनामा करना बताया है जिसका कारण अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विशेष नरमी बरतते हुए एक वित्तीय संस्था द्वारा राजीनामा कर दस वर्ष पुराने प्रकरण के निराकरण में सहयोग किया है। साथ ही अभियुक्त द्वारा भी प्रकरण के निराकरण में सहयोग किया गया है। लोक अदालत पीठ सदस्यगण द्वारा भी अनुशंसा सहित अभियुक्त पर परिव्यय राशि को कम किए जाने के लिए न्यायोचित आधार माना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अभियुक्त से राजीनामा स्वीकार किए जाने हेतु न्यायोचित आधार हैं। साथ ही परिव्यय राशि को भी न्यून कर 500 रुपये के रूप में आदेशित किए जाने हेतु उचित आधार पाया जाता है। उक्त राशि चैक राशि के लगभग 50 प्रतिशत है। अतः यदि अभियुक्त 500 रुपये की राशि परिव्यय के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराए तो राजीनामा स्वीकार किया जावे।

500 रुपये की राशि जमा करने के उपरांत प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।

पीठासीन अधिकारी

पुनश्च:

पक्षकार पूर्ववत।

अभियुक्त के द्वारा रसीद क्रमांक 03 बुक क्रमांक 6888 पर 500 रुपये

जमा कर रसीद प्रस्तुत की।

धारा 147 एन0आई0 एक्ट के अधीन राजीनामा स्वीकार किए जाने हेतु न्यायोचित आधार हैं। अतः बाद तस्दीक राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त विजय शर्मा को चैक क्र0 004231 दिनांक 30.04.07 राशि 10,574 रुपये के संबंध में धारा 138 एन0आई0 एक्ट के आरोप से राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही /—

सदस्य

सही /—

सदस्य

सही /—

पीठासीन अधिकारी

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)